परियोजना का नामः—जनपद देहरादून, उत्तराखण्ड, जौलीग्रान्ट हवाई अडडे के विस्तारीकरण किये जाने हेतु वन भुमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन -

<u>(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)</u>

उत्तराखण्ड राज्य की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थिति के कारण अवागमन हेतु सड़क मार्ग पर ही जनता को निर्भर करना पड़ता है। राज्य का एक बड़ा भाग चीन की सीमा से लगा हुआ है, जिसके विभिन्न पहलुओं के मध्यनजर जॉलीग्रांट हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किया जाना सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। उत्तराखण्ड राज्य पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण समय–समय पर राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ता है। आपदा के समय बचाव कार्य हेतु एवं चारधाम यात्रा तथा पर्यटन को बड़ावा देने के लिए राज्य में हवाई मार्ग अतिआवश्यक है। इस उद्देश्य के दृष्टिगत राज्य में नये हेलीपैडो का निर्माण, मौजूदा हेलीपैडो एवं हवाईपट्टी का सुदृढीकरण का कार्य किया जा रहा है। ए०डी०बी० के वित्तीय सहयोग से 60 नये एवं पूर्व निर्मित हेलीपैड का सुधारीकरण एवं सुदृढीकरण किया जा रहा है। पर्यटन को बड़ावा देने हेतु हिमालय दर्शन की योजना प्राइवेट हेलीकॉप्टर आपरेटर के सहयोग से 08 फरवरी 2015 को प्रारम्भ की गई।

जनपद देहरादून में देश–विदेश से आने वाले पर्यटकों एवं स्थानीय जनता के सुगम आवागमन हेतु जौलीग्रान्ट हवाई अड्डा का निर्माण कराया गया था। वर्तमान में जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे का अन्तरर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विस्तारीकरण किया जाना प्रस्तावित है, साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे एवं पर्यटन को बढावा मिलेगा। इस परियोजना से राज्य का आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सुदृढीकरण होगा एवं राज्य के पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों एवं पर्यटक वाहनों का दबाव भी कम होगा, जिससे प्रशासन को भी राहत मिलेगी।

अतः उपरोक्त प्रयोजन हेतु **5 प्रतियों में प्रस्ताव गठित कर** स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

नरेश चमोली वन संरक्षण विशेषज्ञ पी०एम०यू०, देहरादून	(K. SANTOSH KUMAR) S.A.M.E. FOR DIRECTOR STATE CIVIL AVIATION UTTARAKHAND	ह0/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड सिविल एविएशन अथॉरिटी